



1. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सतत विकास अब केवल विकल्प नहीं बल्कि यही एकमात्र रास्ता है।
2. सांसद बिष्णु पद रे ने मध्योत्तर अण्डमान ज़िले के पंचायती राज संस्थान सदस्यों द्वारा किए गए सामूहिक धरने पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
3. उद्योग निदेशालय की ओर से श्री विजयपुरम में “अण्डमान फूड टेक” कॉन्क्लेव का आयोजन-कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण के लिए नए उत्पादों पर चर्चा की गई।
4. पीसीआर और पराक्रम वाहनों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए जीवन रक्षक तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण।



उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सतत विकास अब केवल विकल्प नहीं बल्कि यही एकमात्र रास्ता है। श्री धनखड़ नई दिल्ली में कल इक्कीसवें अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की सहायता से सतत विकास की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को वैश्विक मंच पर लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यांत्रिक मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों के उभरने से कठिन चुनौतियां जरूर आ रही हैं लेकिन आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर भी मिल रहे हैं।



सांसद बिष्णु पद रे ने कल बिलीग्राउंड बाजार और डिगलीपुर में मध्योत्तर अण्डमान ज़िले के पंचायती राज संस्थान सदस्यों द्वारा किए गए सामूहिक धरने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह विरोध प्रशासन द्वारा उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर ध्यान न दिए जाने और तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन के तहत उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने में समर्थन की कमी के चलते किया गया। धरने के दौरान पी आर आई प्रतिनिधियों ने निधि की

बहाली, शक्तियों का हस्तांतरण, तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन के अनुसार कामकाज, को बहाल करना, 2012 की अधिसूचना के अनुसार समितियों को कार्य आदेश जारी करने के लिए ग्राम पंचायत को शक्ति बहाल करना, समय पर एस्टीमेट तैयार करना और धन का आवंटन जैसे विषयों को सुनिश्चित करना। इस दौरान सांसद ने कहा कि उनके कानूनी रूप से अधिकृत कार्यों और शक्तियों को वापस लेने के कारण, पीआरआई अपने संबंधित गांवों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे वे जनता के सामने एक अस्थिर स्थिति में हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सांसद ने उपराज्यपाल और मुख्य सचिव से इन दबावपूर्ण चिंताओं को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा, मुद्दों को हल करने के लिए, सांसद ने श्री विजयपुरम में पी आर आई प्रतिनिधियों के साथ एक तत्काल बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया है ताकि रचनात्मक बातचीत की सुविधा मिल सके और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि समय पर समाधान से न केवल चल रहे विरोध को समाप्त किया जा सकेगा, बल्कि मध्योत्तर अंडमान के लोगों के हित में स्थानीय शासन का सुचारु संचालन भी सुनिश्चित होगा। सांसद ने प्रशासन से इस मामले को पूरी तत्परता और गंभीरता से लेने की भी अपील की है।



दक्षिण अंडमान ज़िले के लिए किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार का बाल विकास या बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम सात साल कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार सात मार्च तक निर्धारित आवेदन प्रपत्र को भरकर गोलघर स्थित समाज कल्याण निदेशक को डाक या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं।



भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता के सहयोग से उद्योग निदेशालय की ओर से “अण्डमान फूड टेक” कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योग विभाग की सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित

थी। उन्होंने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए खाद्य प्रसंस्करण के लिए नए उत्पादों, खासकर मसालों के बारे में चर्चा की, जिसकी वैश्विक बाजार में बड़ा मूल्य है। उन्होंने स्थानीय किसानों के लिए सही विपणन और प्रसंस्करण की रणनीतियां अपनाने को कहा, ताकि वे अपने उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त कर सकें।

इस अवसर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के उप-कृषि विपणन सलाहकार डॉ. जे पी डोंगरे, मत्स्य विभाग की निदेशक जगताप कल्याणी राजेन्द्र, उद्योग विभाग के निदेशक राकेश दास और भारतीय वाणिज्य मंडल की वरिष्ठ निदेशक मधुपर्णा भौमिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीपो में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना और स्टार्टअप के नए अवसर तलाशना था। कार्यक्रम में लगभग सौ उद्यमियों ने भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के. चन्द्रशेखरन ने उपस्थिति का आभार व्यक्त किया।



पुलिस नियंत्रण कक्ष इकाई द्वारा हाल ही में पीसीआर और पराक्रम वाहनों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए जीवन रक्षक तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह पहल पुलिस अधिकारियों की आपात स्थितियों के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयास का हिस्सा है। जिससे गंभीर परिस्थितियों पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। प्रशिक्षण में प्रमाणित चिकित्सा पेशेवरों और आपातकालीन प्रतिक्रिया विशेषज्ञों ने भाग लिया। सत्र के दौरान पुलिस कर्मियों को सी पी आर, रक्तस्राव नियंत्रण और बेहोश पीड़ितों को संभालने और घुटन की घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। पूरे प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को न केवल आपातकालीन देखभाल के सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में सिखाया गया बल्कि उन्हें वास्तविक स्थितियों में इन तकनीकों को लागू करने का व्यावहारिक अनुभव भी दिया गया।



गाराचरमा में जंग लगे बिजली के खंभों के चैनलों को बदलने का कार्य किया जाएगा। इस सिलसिले में पैंथर-1 और पैंथर-2 ट्रांसमिशन लाइनों के साथ गाराचारमा और डॉलीगंज फीडर से भी बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में गाराचरमा, डॉलीगंज, अट्टम पहाड़,

पुराना पहाड़गांव, और मिनी बे शामिल है। कटौती कल सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगी।

<><><><><><><>

मुख्य सचिव, के प्रत्येक विभाग में तिमाही मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश के अनुसार कल आपदा प्रबंधन निदेशालय ने शिक्षा निदेशालय और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कार्यालय में भूकंप पर चौथी मॉक ड्रिल आयोजित की। विभाग की आपदा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग स्वास्थ्य, अग्निशमन, एन डी आर एफ और बिजली एजेंसियों के सहयोग से ड्रिल की गई। विभाग के कर्मियों ने प्रभावी ढंग से सुरक्षित निकासी और खोज और बचाव अभियान चलाया। घायलों को बचाने और उनका इलाज करने के लिए एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियाँ तुरंत नकली स्थान पर पहुँच गईं। संसाधन विभागों की टीमों ने मॉक ड्रिल के पीड़ितों को खोज और बचाव और प्राथमिक उपचार दिया।

<><><><><><><>